खबर संक्षेप

विकास कार्यों में विलंब करने बालों पर होगी कार्रवाई, सभी कार्य गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करे: गोविंद सिंह राजपूत

भोपाल। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि जो भी विभाग या एजेंसी कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक नहीं करेगा एवं कार्य विलंब से करेगा, उस ठेकेदार एवं अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा की पंचायत एवं ग्रामवासियों की सहमति से कार्यों के स्थल का चयन किया जाए, कहीं सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो तो उसे हटाने की कार्रवाई करें। जो ठेकेदार लगातार कार्यों में विलंब कर रहे हैं उनको ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई करें एवं सभी कार्य गुणवत्ता के साथ शीघ्र करे। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने उक्त निर्देश कलेक्ट्रेट सभाकक्ष सागर में सुरखी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत, जनपद पंचायत अध्यक्ष राम बाबू सिंह, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद सिंह टिंकू राजा, सीईओ जिला पंचायत विवेक के वी, एसडीएम सागर श्रीमती आदिती यादव एसडीम राजगढ़ अशोक सेन, सीईओ जनपद पंचायत, सहित निर्माण एजेंसी और विभागीय अधिकारी मौजूद थे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि सुरखी विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य चल रहे हैं उनका कार्य समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य चाहे वह छोटे हो या बड़े, सभी पर एक आकार की भूमि पूजन लोकार्पण के बोर्ड लगाए। उन्होंने कहा कि लोकार्पण एवं भूमि पूजन निर्माण कार्यों की सूची अलग-अलग लागत राशि के साथ प्रस्तुत करें। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि सुरखी विधानसभा क्षेत्र में जो भी कार्य जिनमें मंदिर निर्माण, चबूतरा निर्माण, विद्यालय निर्माण, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, मंगल भवन निर्माण, नाला निर्माण, स्टॉप डेम, निर्माण कार्य चल रहे हैं सभी गुणवत्ता के साथ बनाएं। उन्होंने कहा कि जहां भी भूमि आवंटन का विवाद है इसका प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करें, जिससे उसका निराकरण किया जा सके।

शासकीय स्कूलों में निःशुल्क साइकिल वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय स्कूलों में निःशुल्क साइकिल वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। दिशा-निर्देश में बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले विद्यार्थी, जो कि शासकीय विद्यालय में कक्षा 6वीं और 9वीं में अध्ययनरत हैं तथा वे जिस ग्राम के निवासी हैं उस ग्राम में शासकीय माध्यमिक विद्यालय-हाई स्कूल संचालित नहीं हैं वे अध्ययन के लिये किसी अन्य ग्राम या शहर के शासकीय स्कूल में जाते हैं उन छात्रों को इस योजना का लाभ कक्षा 6वीं एवं 9वीं में प्रथम प्रवेश पर एक ही बार मिलेगा। इन कक्षाओं में पुनः प्रवेश लेने पर साइकिल की पात्रता नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे विद्यार्थी जो शासकीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं एवं 9वीं में अध्ययनरत हैं उस गांव से उनके निवास की दूरी 2 किलोमीटर की दूरी से अधिक हो उन्हें ही साइकिल की पात्रता होगी। ग्रामीण क्षेत्र में कन्या छात्रावास में अध्ययनरत छात्राएं जिनके माध्यमिक शाला और हाई स्कूल छात्रावास से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर अधिक दूरी पर है यह साइकिलें छात्रावास को आवंटित की जायेंगी।

दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्यवाही के निर्देश

राज्य सरकार खिवनी अभयारण्य के प्रभावितों के साथ है : मुख्यमंत्री

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खिवनी अभयारण्य के लिए वन विभाग द्वारा खातेगांव इछावर क्षेत्र मे की गई कार्यवाही से प्रभावित क्षेत्र के जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ समत्व भवन में भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संवेदनशीलता से शिकायतों और पीड़ा को सुना। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्रवाई पर खेद व्यक्त करते हुए, स्थिति का उचित समाधान निकालने, शिकायतों की जांच करवाने, दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्यवाही करने और क्षेत्र के लोगों को सभी शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावितों के साथ है। यह सुनिश्चित किया जाएगा की बरसात में किसी को कोई तकलीफ ना हो। राहत के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जांएगी।

प्रदेश की औद्योगिक विकास दर को गति देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश की कृषि विकास दर के समान औद्योगिक विकास दर को आगे बढ़ाने के लिए के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इसी उद्देश्य से उद्योग व्यापार और निवेश गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर समिट आयोजित करने और देश-विदेश के प्रमुख औद्योगिक व्यापारिक केंद्रों से संपर्क का क्रम जारी है। राज्य सरकार की इस पहल का प्रदेश को लाभ भी मिल रहा है। इसी क्रम में आज सूरत में ÷मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर इंटरएक्टिव सेशन÷ रखा गया है। यह आयोजन उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2025 अभियान की श्रृंखला में बेंगलुरु के बाद दूसरा बड़ा संवाद है। क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिक समूह से जुड़ाव बढ़ाना और प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करना तथा निवेश को सुगम बनाना इस अभियान का उद्देश्य है। सूरत देश का प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। वहां के उद्योग व्यापार जगत के सहयोग से प्रदेश में निवेश गतिविधियों को प्रोत्साहन मिले, इस उद्देश्य से वहां समिट आयोजित किया गया है। राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सूरत प्रस्थान से पहले मीडिया के लिए जारी संदेश में यह विचार व्यक्त किऐ।

रीवा में प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात का किया श्रवण

'मन की बात' देश की आत्मा से जुड़ाव का माध्यमः प्रेरणा, दिशा और विश्वास का स्रोतः उप मुख्यमंत्री शुक्ल

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

प मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि 'मन की बात' सिर्फ संवाद नहीं, यह देश की आत्मा से जुड़ाव का माध्यम है – प्रेरणा, दिशा और विश्वास का स्रोत है। प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन सदैव प्रेरणादायक होता है। 'मन की बात' की 123वीं कड़ी ने जन-मन में नई ऊर्जा का संचार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धियों, योग और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों के साथ-साथ आपातकाल की विभीषिका को भी याद किया। आपातकाल का दौर लोकतंत्र के लिए एक काली रात था, जिसे देशवासियों ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से समाप्त किया। यह हमारी लोकतांत्रिक चेतना की अमिट मिसाल है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने रीवा के बूथ क्रमांक 111 स्थित निवास में प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम ÷मन की बात÷ का श्रवण किया। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश के बालाघाट की बेटी सुसूमा उइके, जिन्होंने स्व-सहायता समूहों के माध्यम से मशरूम उत्पादन, पशुपालन और 'दीदी केंटीन' जैसे उद्यमों से आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की।

प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में सुसूमा उइके का उल्लेख प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। साथ ही यह अन्य महिलाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि भारत का 'ट्रेकोमा मुक्त' घोषित होना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह न केवल हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की सतत मेहनत का परिणाम है वरन् यह 'स्वच्छ भारत अभियान' और 'जल जीवन मिशन' की सामूहिक सफलता का भी परिचायक है। यह जनसहभागिता आधारित स्वास्थ्य सुधार मॉडल का उत्कृष्ट उदाहरण है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 'फिटनेस के लिए 10 प्रतिशत तेल कम' जैसे छोटे लेकिन प्रभावशाली सुझाव हर घर को स्वस्थ जीवनशैली की ओर ले जाने का सरल मंत्र हैं।

बालाघाट की सुमा दीदी बनीं बिजनेस वुमन

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल/बालाघाट।

जज़्बा हो तो हमारी माताएं-बहनें भी बिज़नेस वुमन बन सकती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये बात कहते हुए मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले की एक महिला उद्यमी, सुमा उईके का विशेष रूप से उल्लेख किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बताया कि कटंगी विकासखंड के ग्राम भजियापार की रहने वाली सुमा उईके ने कैसे अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और आजीविका मिशन की मदद से खुद को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम 'मन की बात' में नाम का ज़िक्र होने के बाद से सुमा उईके के साथ साथ पूरे बालाघाट में उत्साह का माहौल है। सुमा उईके कभी सिर्फ अपने घर-गृहस्थी के कामों तक सीमित थीं, लेकिन आजीविका मिशन के कर्मियों से मिले मार्गदर्शन से उन्हें स्व-सहायता समूह का महत्व पता चला। इसके बाद उन्होंने आस-पास की महिलाओं को संगठित कर आदिवासी आजीविका विकास स्व-सहायता समूह का गठन किया, जिसकी वह अध्यक्ष बनीं। समूह के माध्यम से उन्होंने आर-सेटी से ऑर्गेनिक मशरूम उत्पादन और ष्ट्रञ्जष्ट से पशुपालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वर्ष 2021 में उन्होंने 2000 रुपये की ऋण सहायता से मशरूम उत्पादन की शुरुआत की। हालांकि लॉकडाउन के कारण यह कार्य बाधित हुआ, लेकिन सुमा दीदी ने हार नहीं मानी।

प्रधानमंत्री मोदी की बातों से विद्यार्थियों को मिलता उत्साह और प्रेरणाः राज्यपाल

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की मन की बात ज्ञान की बातों का कार्यक्रम है। इसमें ज्ञान और संस्कार की बातें होती है। देश के कोने-कोने में हो रहे प्रेरक कार्यों और प्रसंगों की जानकारी होती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की बातों से विद्यार्थियों को नया उत्साह और प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी आदतें बड़े बदलाव का कारण बनती है। कार्यक्रम ज्ञान की बातों का खजाना है। इसलिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम सुनना आदत बनाई जाए। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के सभी छात्र-छात्राओं और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 9 से लेकर 12 वीं तक के सभी विद्यार्थी प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम में शामिल हो। कोई छात्र-छात्रा कार्यक्रम से वंचित नहीं हो। राज्यपाल पटेल ने यह बात भोपाल में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ चर्चा में

कहीं। राज्यपाल एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोपाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को बच्चों के साथ सुनने के लिए पहुँचे थे। इस अवसर पर राज्यपाल पटेल ने विद्यालय के बालिका छात्रावास का निरीक्षण भी किया। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की मन की बातें गागर में सागर के समान होती है। उसमें अच्छे जीवन के मंत्र होते हैं। उत्कृष्ट कार्यों का बखूबी जिक्र होता है। नवाचार और सफलता के किस्से होते हैं। विभिन्न विषयों की वृहद जानकारियां अल्प अवधि में उपलब्ध हो जाती है, जो हमें जीवन की सही दिशा दिखाती है। अनेक चुनौतियों और समस्याओं के समाधान भी हमें कार्यक्रम में मिल जाते हैं। राज्यपाल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में ग्रामीण आजीविका, विकास और जन कल्याणकारी कार्यों का विवरण मिलता है। अत्यंत प्रेरणादायी और मार्गदर्शी विकास की नई पहल और सफलता की कहानियों का पता चलता है। उन्होंने प्रदेश की समस्त पेसा ग्राम सभाओं के पदाधिकारियों से अपील की है कि प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम प्रसारण दिवस पर ग्राम सभाओं का आयोजन करने का प्रयास करें। कार्यक्रम में सहभागिता से ग्राम सभा सदस्यों को ग्राम विकास और कल्याण प्रयासों का दिशा का दर्शन होगा। विकास के लिए सामूहिक प्रयासों की प्रेरणा मिलेगी। राज्यपाल पटेल ने कहा कि सार्थक ज्ञान वही है जो संस्कार युक्त हो। उच्च शिक्षित होना पर्याप्त नहीं है। अच्छा जीवन जीना महत्त्वपूर्ण है, जिसमें दायित्व का बोध हो। उन्होंने कहा कि संस्कारित जीवन के लिए बचपन से ही प्रयास किए जाना जरुरी है। उन्होंने आवासीय विद्यालय के शिक्षकों, प्रबंधकों और विद्यार्थियों को मिलकर संकल्प के साथ इस दिशा में प्रयास करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि दिन की अच्छी शुरुआत, अच्छे जीवन का सबक है। सूर्योदय के साथ प्रातः विधि के बाद कक्ष की सफाई और उसे सुव्यवस्थित करें।

एसआरएस रिपोर्ट पर पटवारी बोले- चाय-नाश्ते और चर्चा में खर्च हो रहा हेल्थ बजट

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

दो दिन पहले जारी हुई सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट में शिशु और मातृ मृत्यु दर के मामले में मध्यप्रदेश सबसे खराब राज्यों में फिर नजर आया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एसआरएस की रिपोर्ट को लेकर मप्र सरकार और स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। पटवारी ने सीएम डॉ. मोहन यादव को लेटर लिखा है। पटवारी ने अपने पत्र में लिखा- सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) की ताजा रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है कि हमारे प्रदेश में हर 1000 में से 40 बच्चे अपना पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाते। पटवारी ने आगे लिखा- आपकी सरकार जिस कागजी विकास की गंगा बहा रही है, वह कितनी गहरी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हम हर महीने कर्ज लेकर इस विकास-रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी में 4500 करोड़ का सालाना स्वास्थ्य बजट भी है, लेकिन यह पैसा जाता कहां है? क्या यह कुपोषण के ऐसे घोटालों में समा जाता है।

पोषण से परिवर्तन की ओर बच्चों के स्वास्थ्य सुधार राज्य स्तरीय कार्यशाला आज

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में सुपोषित मध्यप्रदेश की दिशा में बढ़ते कदम को मजबूत करने एवं प्रभावी हस्तक्षेपों की सुनियोजित कार्ययोजना तैयार करने के उद्देश्य से ÷पोषण से परिवर्तन की ओर÷ 30 जून 2025 को होटल लेक व्यू रेजिडेंसी, श्यामलाहिल्स, भोपाल में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास श्रीमती रश्मि अरुण शमी तथा आयुक्त, महिला एवं बाल विकास श्रीमती सूफिया फारुकीवली द्वारा प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दिया जाएगा। कार्यशाला में प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों के साथ विषय-विशेषज्ञों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।

राष्ट्रीय सर्वे में दिखा प्रभावी सुधार

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-3 (2005-2006) से सर्वे- 5 (वर्ष 2020-2021) के दौरान बच्चों के पोषण स्तर में व्यापक रूप से सुधारपरिलक्षित हुआ है। इन आंकड़ों के अनुसार कम वजन में लगभग 45त्न, दुबलापन में 46त्न एवं ठिगनापन में 29त्न तक का सुधार प्रदर्शित हो रहा है। कार्यशाला में इन्ही आंकड़ों के विश्लेषण एवं सुपोषित मध्यप्रदेश की आगामी कार्ययोजना के बारे में चर्चा की जाएगी। बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए जिलों द्वारा स्थानीय स्तर पर नवाचार किए जा रहे हैं। कार्यशाला के दौरान इन नवाचारों, विशेष प्रयासों का प्रस्तुतीकरण भी किया जाएगा। झाबुआ से कुपोषित बच्चों के पोषण प्रबंधन के लिये मोटीआई, देवास जिले के मिशन किलकारी अंतर्गत स्पेशल NRC जैसे प्रयासों को प्रस्तुत किया जाएगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आदिवासी या महिला नेता पर लगा सकती है दांव

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

भारतीय जनत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का फैसला अब तीन जुलाई या जुलाइ के पहले सप्ताह में कभी भी हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। संभवतः एक जुलाई को चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाए और तीन जुलाई को भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पद के नाम को अंतिम रूप दे दिया जाए। सूत्रों के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जुलाई के पहले सप्ताह में कराया जा सकता है। मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव अधिकारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं जो एक या दो जुलाई को भोपाल आने वाले हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जुलाई के पहले सप्ताह में ही पूरी हो जाएगी। ऐसा इसलिए भी संभव है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भाजपा ने संगठन चुनाव की प्रक्रिया रोक थी दी। लेकिन अब चुनाव की प्रक्रिया दो दिन पहले फिर शुरू कर दी है। एक राज्य में चुनाव की तारीख का भी ऐलान हो चुका है, वहीं महाराष्ट्र सहित तीन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है।

नई रणनीति के तहत बदलेगा नेतृत्व समीकरण

प्रदेश संगठन में फिलहाल सामान्य वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष, ओबीसी से मुख्यमंत्री और अनुसूचित जाति वर्ग से उपमुख्यमंत्री हैं। ऐसे में संगठन संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी आदिवासी या महिला नेता को सौंपे जाने की संभावना है। अंतिम निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लेगा।

प्रदेश परिषद के 345 सदस्य करेंगे चयन

प्रदेश अध्यक्ष के चयन के लिए भाजपा द्वारा पहले ही जिला अध्यक्षों के साथ प्रदेश परिषद के 345 सदस्य चुन लिए गए हैं। दो विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया गया है, जिसके तहत परिषद सदस्य चुने गए हैं। आरक्षित वर्गों (एससी-एसटी) के लिए सीटों के अनुरूप संबंधित वर्ग से ही परिषद सदस्य बनाए गए हैं।

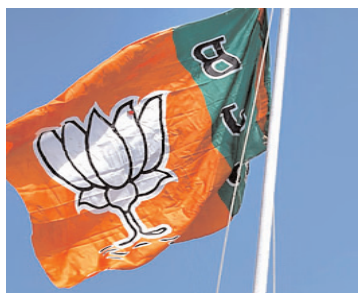

महिलाओं और ओबीसी वर्ग को भी समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। मध्यप्रदेश भाजपा में अधिकांश बार प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ है। केवल दो बार ही मतदान की स्थिति बनी थी। पहली बार 1990 के दशक में लखीराम अग्रवाल और कैलाश जोशी के बीच, और दूसरी बार वर्ष 2000 में शिवराज सिंह चौहान और विक्रम वर्मा के बीच, जिसमें वर्मा विजयी हुए थे।

आधा दर्जन से अधिक दावेदार सक्रिय

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए वर्तमान अध्यक्ष वीडी शर्मा स्वयं बड़े दावेदार हैं। इसके साथ पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ला, बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल और पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया के साथ सांसद सुधीर गुप्ता के नाम भी इस दौड़ में बने हुए हैं। महिला अध्यक्ष बनाए जाने की स्थिति में पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, सांसद कविता पाटीदार, लता वानखेड़े के नाम चर्चाओं में हैं। अगर भाजपा बाबा साहब अंबेडकर को देखकर अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति वर्ग से बनाती है तो भाजपा अजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, विधायक प्रदीप लारिया के नाम भी चर्चा में हैं। भाजपा द्रौपदी मुर्मु को राष्ट्रपति बनाकर हर चुनाव में आदिवासियों को सम्मान देने की बात करती है। भाजपा मध्यप्रदेश में आदिवासियों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए बैतूल से सांसद केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, खरगोन सांसद गजेन्द्र पटेल, मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी के नाम पर विचार कर रही है। महिला वर्ग को भी साधने के लिए सावित्री ठाकुर को भी मौका दिया जा सकता है।

भोपाल में 90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज को लेकर एक्शन, सीएम ने 8 अफसरों को किया सस्पेंड

भोपाल। भोपाल के 90 डिग्री एंगल वाले ऐशबाग आरओबी के निर्माण में हुई गंभीर लापरवाही पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 8 अफसरों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार रात मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि मैंने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट के आधार पर लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दो सीई सहित सात इंजीनियर्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। एक सेवानिवृत एसई के खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी। इस प्रोजेक्ट में आरओबी का त्रुटिपूर्ण डिजाइन प्रस्तुत करने पर निर्माण एजेंसी एवं डिजाइन कंसल्टेंट, दोनों को ब्लैक लिस्ट किया है। आरओबी में आवश्यक सुधार के लिए कमेटी बनाई गई है। सुधार के बाद ही आरओबी का लोकार्पण किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग नीरज मंडलोई ने बताया कि जिन अफसरों पर कार्रवाई हुई है। उनके खिलाफ कल आरोप तय किए जाएंगे। ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण 21 मई 2022 को शुरू था। समय-सीमा से प्रोजेक्ट एक साल देरी से चल रहा है। 17 करोड़ 37 लाख की लागत वाले ब्रिज का निर्माण अगस्त 2024 में पूरा होना था। लेकिन, जून 2025 में भी इसे बनाने की प्रक्रिया जारी है। बता दें, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) से जांच करवाई थी। एनएचएआई ने ब्रिज को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें 35-40 किमी प्रति घंटा से अधिक गति से गाड़ी नहीं चलाने का सुझाव दिया गया है। इससे अधिक स्पीड में गाड़ी चली तो हादसा होने का खतरा है। ऐसे में इस ब्रिज को रिडिजाइन करने का फैसला लिया गया है।